नवभारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

नक्सल मुक्त भारत : सुरक्षा, विकास का नया अध्याय

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 30 मार्च 2026 को लोकसभा में भारत को 'नक्सल मुक्त' घोषित करना केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के आंतरिक सुरक्षा इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाना चाहिए. दशकों तक देश के अनेक हिस्सों—विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश,में नक्सलवाद ने न केवल कानून-व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि विकास की धारा को भी बाधित किया. ऐसे में इस समस्या के समाधान का दावा अपने आप में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है.

सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े इस परिवर्तन की पुष्टि करते हैं. कभी 126 जिलों तक फैला नक्सल प्रभाव अब शून्य पर सिमट गया है—कम से कम 'अत्यधिक प्रभावित' श्रेणी में. 706 नक्सलियों का मुठभेड़ों में मारा जाना, 4,839 का आत्मसमर्पण और 2,218 की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि सुरक्षा बलों ने लगातार और सुनियोजित अभियान चलाया. लेकिन केवल इन आंकड़ों के आधार पर इस सफलता को समझना अधूरा होगा.

असल में, इस पूरे अभियान की रीढ़ रहा है 'सुरक्षा और विकास' का दोहरा मॉडल. एक ओर जहां सुरक्षा बलों ने सख्ती से नक्सली ढांचे को तोड़ा, वहीं दूसरी ओर सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया. लगभग रुपए 20,000 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण, स्कूलों की स्थापना और संचार सुविधाओं का विस्तार, इन सबने उन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई. बस्तर जैसे इलाके, जो कभी 'रेड कॉरिडोर' के प्रतीक थे, अब विकास के नए केंद्र बनने की ओर अग्रसर हैं.

हालांकि, इस उपलब्धि का मूल्यांकन करते समय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठते हैं. क्या नक्सलवाद का पूर्ण अंत वास्तव में हो चुका है, या यह केवल उसके संगठित स्वरूप का विघटन है. इतिहास बताता है कि विचारधाराएं केवल सैन्य कार्रवाई से समाप्त नहीं होतीं. वे सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, स्थानीय असंतोष और शासन की विफलताओं से पुनः जन्म ले सकती हैं. ऐसे में यह आवश्यक है कि सरकार विकास कार्यों को निरंतरता दे और स्थानीय समुदायों के विश्वास को बनाए रखे.

गृहमंत्री द्वारा 'अर्बन नक्सल' पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी भी एक नई बहस को जन्म देती है. यह सच है कि किसी भी प्रकार की हिंसक विचारधारा को वैचारिक समर्थन देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है, लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि वैचारिक असहमति और लोकतांत्रिक आलोचना को 'नक्सल समर्थन' के दायरे में न रखा जाए. लोकतंत्र की मजबूती इसी संतुलन में निहित है.

राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार ने इसे अपनी निर्णायक नीति और मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम बताया है, जबकि विपक्ष इसे आंकड़ों और परिभाषाओं के खेल के रूप में देख सकता है. ऐसे में पारदर्शिता और स्वतंत्र मूल्यांकन इस उपलब्धि की विश्वसनीयता को और मजबूत करेंगे. बहरहाल,'नक्सल मुक्त भारत' का यह दावा एक नई शुरुआत का अवसर है. यह केवल सुरक्षा की जीत नहीं, बल्कि उस भारत के निर्माण की दिशा में कदम है जहां विकास, न्याय और समान अवसर हर नागरिक तक पहुंचे. यदि सरकार इस उपलब्धि को स्थायी बनाना चाहती है, तो उसे बंदूक की जगह भरोसे, और कार्रवाई के साथ संवेदनशीलता को भी समान महत्व देना होगा. तभी यह घोषणा इतिहास में एक स्थायी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो सकेगी.

ओलंपिक सपनों की ओर एक मजबूत कदम

जैसे-जैसे भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयासरत है, वैसे-वैसे प्रतिभाओं का दायरा बढ़ाना और भी आवश्यक हो जाता है. इसका अर्थ है देश के हर कोने तक पहुंचना और यह सुनिश्चित करना कि युवा खिलाड़ी-विशेषकर जनजातीय समुदायों से- अवसरों से वंचित न रहें. जनजातीय खेलों की शुरुआत इसी सोच का परिणाम है और यह भारत के विकसित हो रहे खेल तंत्र की मजबूती को दर्शाता है. खेल उत्कृष्टता की यात्रा अक्सर उन गाँवों और समुदायों से शुरू होती है जहाँ सपने तो होते हैं, लेकिन अवसर सीमित होते हैं. खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के माध्यम से सरकार खेल को इन्हीं क्षेत्रों तक पहुँचा रही है.

डॉ. मनसुख मंडविया

भारत की खेल यात्रा अद्भुत विविधताओं से भरी हुई है. उत्तर-पूर्व के पहाड़ों से लेकर मध्य भारत के जंगलों तक, हमारे देश के हर कोने में प्रतिभा मौजूद है. खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत को अब आठ वर्ष हो चुके हैं, और इतने कम समय में यह एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हो चुका है. युवा खेल, विश्वविद्यालय खेल, बीच गेम्स और विंटर गेम्स जैसे विभिन्न आयामों के माध्यम से, खेलो इंडिया ने देशभर के युवाओं की विविध प्रतिभाओं को पहचानने और उभारने में सफलता प्राप्त की है. खेलो इंडिया जनजातीय खेल (केआईटीजी) का समावेश इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है. इसका पहला संस्करण 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 3,000 खिलाड़ी भाग लेंगे. इन खेलों में सात पदक खेल शामिल होंगे — एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती.

इन खेलों का आयोजन बस्तर क्षेत्र के जनजातीय बहुल जिलों, जो प्राचीन दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा हैं, के साथ-साथ सरगुजा क्षेत्र, रायगढ़ और मानपुर जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा. यह केवल एक और खेल प्रतियोगिता की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत भारत के खेल पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) को व्यापक बनाते हुए हर खिलाड़ी तक अवसर पहुंचाना है — चाहे वह किसी भी भौगोलिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आए. सीधे शब्दों में कहें तो यह हाशिए पर पड़े खिलाड़ियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है. जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने लंबे समय से देश को गौरवान्वित किया है. राजस्थान के महान तीरंदाज लिम्बाराम से लेकर झारखंड की तीरंदाजी स्टार दीपिका कुमारी तक, और अनेक हॉकी खिलाड़ियों से लेकर ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू तक, उनकी उपलब्धियाँ लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं. ये उदाहरण इन क्षेत्रों में निहित अपार संभावनाओं को दर्शाते हैं.

कई जनजातीय क्षेत्र ऐसे भी हैं जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते रहे हैं. इन क्षेत्रों के युवाओं के लिए पहचान और विकास के अवसर सीमित रहे हैं. ऐसे में, इन क्षेत्रों में संगठित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मोड़ने का कार्य करता है. यह अनिश्चितता को अवसर में और अलगाव को समावेशन में बदलने का प्रयास है. वास्तव में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण — 'खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत' — आज साकार हो रहा है. खेल आज एक सशक्त माध्यम और समान अवसर प्रदान करने वाला साधन बन चुका है, जो वंचित वर्गों के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का अवसर देता है. जनजातीय क्षेत्रों में खेलो इंडिया का विस्तार इसी दृष्टि का स्वाभाविक विस्तार है और यह विश्वास को मजबूत करता है कि खेल राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.

खेलो इंडिया जनजातीय खेलों का आयोजन स्थानीय खेल पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा. इससे जनजातीय क्षेत्रों में खेल अवसंरचना का विकास और उन्नयन होगा, साथ ही स्थानीय कोच, प्रशिक्षक और सहयोगी कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे. स्कूलों और सामुदायिक संस्थानों को दैनिक जीवन में खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर एक स्थायी और समावेशी खेल संस्कृति विकसित हो सके. ये खेल केवल एक बार आयोजित होने वाले आयोजन नहीं हैं, बल्कि इन्हें खेलो इंडिया के वार्षिक कैलेंडर में स्थायी स्थान दिया जाएगा. इससे देशभर के जनजातीय खिलाड़ियों को नियमित मंच मिलेगा, जो उनके दीर्घकालिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है.

(लेखक भारत सरकार में युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं.)

सभी धर्म प्रेम, करुणा, मानवता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का समर्थन करते हैं

भारतीय ज्ञान प्रणाली और अनुच्छेद 28 का संवैधानिक दायित्व

डॉ. दिलीप सिंह

> सरकारी धन मूलतः उन करों से आता है, जो भारत के सभी नागरिकों से, उनके धर्म, जाति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, एकत्र किए जाते हैं। इसलिए, सार्वजनिक धन से समर्थित संस्थानों में किसी विशेष धर्म से जुड़े शिक्षण की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाता है, विशेषकर तब जब भारतीय राज्य संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है।

क्या ज्ञान किसी विशेष समूह, क्षेत्र या धर्म का होता है? इसका उत्तर देखने में हाँ लग सकता है, लेकिन मूलतः यह नहीं होना चाहिए। यह हाँ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से ज्ञान तक पहुँच अक्सर कुछ विशेष समूहों तक सीमित रही है, जबकि अन्य को धर्म, क्षेत्र, जाति या लिंग के आधार पर इससे वंचित किया गया। ऐसा बहिष्कार अनिवार्य रूप से ज्ञान-सम्पन्न और ज्ञान-वंचित के बीच एक खाई पैदा करता है। परंतु सिद्धांततः ज्ञान सार्वभौमिक है। यह न तो धर्म से बंधा है, न भूगोल से और न ही राजनीतिक सीमाओं से। ज्ञान मानवता की साझा धरोहर है, जिसका उद्देश्य समाज के सामूहिक उत्थान और कल्याण के लिए है। इसके साथ ही, यह भी सत्य है कि नैतिकता और मूल्य व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। लगभग सभी धर्म प्रेम, करुणा, मानवता, न्याय और पारस्परिक सम्मान जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का समर्थन करते हैं, और यही मूल्य संविधान की प्रस्तावना में भी निहित हैं, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक है।

भारत की बौद्धिक परंपराओं के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग की स्थापना की। इस प्रभाग का आदर्श वाक्य है-आइए, हम उस ज्ञान की ओर अग्रसर हों जो सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। यहाँ सभी शब्द स्वाभाविक रूप से समावेशिता का संकेत देता है—अर्थात हर धर्म, संस्कृति और दर्शन के लोगों को समाहित करना। किंतु वर्तमान में क्ष्यूर मंच पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों पर दृष्टि डालने से कुछ चिंताएँ सामने आती हैं। पोर्टल के अनुसार, अनेक पाठ्यक्रम आयुर्वेद, योगसूत्र, भगवद्गीता, वैष्णव वेदांत, पाणिनि व्याकरण, पारंपरिक खगोलशास्त्र, श्रीमद्भागवतम और सांख्य दर्शन जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, क्ष्यूर प्रभाग ने कई वैदिक और संस्कृत विश्वविद्यालयों तथा सिद्धांत और सरयू फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (रूम) भी किए हैं। निस्संदेह, ये विषय भारत की बौद्धिक धरोहर के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन वर्तमान संरचना मुख्यतः एक विशेष धार्मिक या दार्शनिक धारा से जुड़े ज्ञान पर अधिक बल देती प्रतीत होती है। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है- यदि क्ष्यूर का उद्देश्य सभी का कल्याण है, तो क्या इसके ढाँचे में अन्य समुदायों—जैसे सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई आदि—की ज्ञान परंपराओं और योगदानों को भी समान रूप से स्थान नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है? सभी के कल्याण की अवधारणा को वास्तविक रूप से साकार करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली एक समावेशी मंच के रूप में विकसित हो, जो भारत की विविध ज्ञान परंपराओं का प्रतिनिधित्व करे, न कि किसी एक धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण तक सीमित दिखाई दे। तभी यह ज्ञान की सार्वभौमिक भावना को सही अर्थों में प्रतिबिंबित कर सकेगी और कोई भी समुदाय स्वयं को इससे बाहर महसूस नहीं करेगा। भारत का संविधान, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत, उन शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा-पाठ के आयोजन पर प्रतिबंध लगाता है, जो पूर्णतः राज्य के धन से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आंशिक रूप से सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में भी किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक ढाँचा स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। चयन की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। भारत अत्यधिक विविधता वाला देश है, जहाँ अनेक क्षेत्र, संस्कृतियाँ और आस्थाएँ मौजूद हैं। यहाँ कोई एक समान विश्वास प्रणाली नहीं है जो पूरे समाज को परिभाषित करे। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज जन्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर भी विभाजित रहा है। इसी प्रकार, अंतर-धार्मिक संबंधों में भी कभी-कभी श्रेष्ठता और हीनता की धारणाएँ उभरती हैं, जो प्रायः अनुयायियों की संख्या या सामाजिक प्रभुत्व से प्रभावित होती हैं। यह मानसिकता मूलतः असामाजिक है और विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में संघर्ष और विवाद को जन्म दे सकती है। जब एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है और फिर उसी क्रम में अन्य को, तो यह एक ऐसी श्रेणीबद्धता उत्पन्न करता है जो एकता के बजाय विभाजन को बढ़ावा देती है। विद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसे स्थान हैं जहाँ विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थी एक साथ आते हैं। संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी छात्र को जाति, पंथ, नस्ल, धर्म, क्षेत्र या जन्मस्थान के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

क्या बंगाल में बदलाव की आशा की जाए

बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या वहां की जनता टीएमसी शासन के 15 वर्षों के कामकाज के आधार पर वोट देगी? क्या एसआईआर चुनाव नतीजों पर प्रभाव डालेगा अथवा रेवड़ी बांटने वाली अपनी योजनाओं से ममता बनर्जी अपनी गद्दी सलामत पाएंगी? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता इमोशनल ब्लैकमेल कर चुनाव जीतती हैं. पिछली बार उन्होंने पैर में पट्टी बांधी थी, अब कोई नया खेल करेंगी. बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार टीएमसी को हराया जाए लेकिन ममता हर बार भारी पड़ जाती हैं. उन पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं लेकिन ममता के पास इसका जवाब है रेवड़ी या फ्रीबीज! उनकी लक्ष्मी भंडार योजना से महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जमा हो जाते हैं. इस योजना पर 27,500 करोड़ रुपये खर्च आता है. यह रकम बंगाल के 2026-27 के 3.96 लाख करोड़ रुपये की लगभग 7 प्रतिशत है. ऐसी योजना उधारी के पैसों से चलती है और राज्य पर कर्ज का बोझ व वित्तीय संकट बढ़ता चला जाता है. राज्य में औद्योगिकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है. कृषि उपज प्रक्रिया में भी कोई निवेश नहीं किया गया. बंगाल में संसाधनों की कमी नहीं है. वहां निवेश, आधुनिकीकरण तथा अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी नहीं है. बंगाल में देश का 80 प्रतिशत जूट पैदा होता है. इस लिहाज से इस राज्य को विश्व की जूट राजधानी कहा जाना चाहिए. अधिकांश जूट, अनाज और शक्कर के बोरे बनाने के काम आता है, जिसे सरकार खरीदती है. बांग्लादेश ने आधुनिकीकरण से जूट के अंतरराष्ट्रीय बाजार पर कब्जा कर लिया, लेकिन बंगाल ऐसा नहीं कर पाया. चाय उत्पादन में भी श्रीलंका ने बंगाल को पीछे छोड़ दिया. दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला हुआ है लेकिन ब्लेंडर उसमें भी मिलावट कर देते हैं. दीर्घावधि निवेश के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं समझा जाता. रतन टाटा ने लेफ्ट की सरकार के समय सिंगूर में टाटा मोटर्स का कारखाना लगाया था लेकिन ममता बनर्जी के आंदोलन की वजह से टाटा को मजबूर होकर कारखाना हटाना पड़ा था.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

निशानेबाज

ट्रंप को सीधे शांति वार्ता में आसानी तैयार हैं बोमन व स्मृति

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, अमेरिका के हमलावर राष्ट्रपति ट्रंप को यदि ईरानियों से शांति वार्ता करनी थी तो पाकिस्तान को बिचौलिया बनाने की बजाय भारत की मदद लेते. उन्हें शायद पता नहीं कि भारत ही विश्व का सबसे बड़ा शांतिप्रिय देश है, जहां फिल्मों में भी ओम शांति ओम का गीत गूंजता है. यहां शांतिलाल और शांतिबाई जैसे लोग मिल जाएंगे. मशहूर डायरेक्टर वी. शांताराम का नाम कौन नहीं जानता! राजा शांतनु के खानदान में भी महाभारत होकर रहा.'

हमने कहा, 'अपनी बात सही तरीके से रखिए. भारत सरकार ट्रंप को बता सकती है कि भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने दुनिया को शांति, करुणा और सद्भावना का संदेश दिया था. हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे. वह हर स्वाधीनता दिवस समारोह में शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाया करते थे. हमारे अनुष्ठानों में शांति पाठ पढ़ा जाता है, जिसमें पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक शांति की कामना की गई है. हम सभी की सुख-शांति के लिए कहते हैं- सर्वे सुखिना भवंतु, सर्वे संतु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चिद दुख भाग्भवेत!'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, भारत शांति के लिए नैतिक और धार्मिक उपदेश दे सकता है लेकिन पाकिस्तान जैसी दलाली नहीं कर सकता. यदि ट्रंप को मोदी जैसा मेडिटेशन करना आता तो वह शांति का अर्थ समझते. ट्रंप को सम्राट अशोक के बारे में बताया जाना चाहिए, जिन्होंने कलिंग (ओडिशा) पर आक्रमण किया था. वहां हुए भीषण नरसंहार और लाखों लोगों के खून की नदियां देखकर उनका मन अत्यंत विचलित हुआ तो उन्होंने शांति की सीख देने वाले बौद्ध धर्म को अपना लिया.'

हमने कहा, 'इतनी पुरानी मिसाल मत दीजिए. यह बताइए कि इस समय ट्रंप ईरानियों से शांति वार्ता कैसे और कहां करें?'

पड़ोसी ने कहा, 'यदि ट्रंप को सीधे आमने-सामने शांति वार्ता करनी है तो भारत चले आएं. महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चढ़ाने के बाद सीधे बॉलीवुड जाएं. वहां बोमन ईरानी, अरुणा ईरानी, डेजी ईरानी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीवी सीरियल अभिनेत्री स्मृति ईरानी से शांति वार्ता कर सकते हैं. यहां ईरानियों की कोई कमी नहीं है.'

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12215 - डॉ. सागर खादीवाला

1		2	3	4		■	5
	■	6			■	7	
8	9	■	■	10	11		■
■	12		■	13			■
14		■	15	■		■	16
17				■	18	19	
20		■	21	22	■	23	
	■	24					■

ऊपर से नीचे
1. वकालत 2. बुरी आदत (उर्दू) 3. थप्पड़ मारने से उत्पन्न शब्द 4. किसी रास्ते से कहीं जाने या घुसने की रुकावट 5. बरछा, नेजा 7. तुच्छता, अभाव, कमी 9. बलपूर्वक किसी के वस्त्र उतारना 11. अमीर 14. व्यवहार, चालचलन 15. उपासना, पूजा 16. सुंदर शब्द वाला, शंख (सं.) 19. भारी वस्तु के गिरने का शब्द 22. राजा, सरदार

बाएं से दाएं
1. किसी मुकदमे की पैरवी करने का वकील को दिया गया अधिकार-पत्र (उर्दू) 6. बघारे, छौंक 7. बहाना, मिस 8. एक सदाबहार मीठा फल या उसका वृक्ष 10. बांधने की वस्तु, रस्सी आदि 12. ध्वनि, गुंजार, आवाज 13. गरीबी, नम्रता 14. कष्टसूचक श्वास, उसांस 17. तीखे स्वाद वाला 18. जुतना, जुड़ना 20. लड़ाई, युद्ध, जंग 21. पृथ्वी 23. मतवाले हाथियों की कनपटी से निकलने वाला द्रव, हर्ष, उन्माद 24. जो एक ही बार दिया जाए या किया जाए, जिसका आवर्तन न हो

Solution 12214

मि	सि	ल	■	क	ल	प	ना
ह	त	■	मा	त	ह	त	■
च	म	की	ला	■	का	न	न
ना	■	क	■	बा	ना	■	क्शा
■	स	र	ह	द	■	अ	■
आ	दी	■	■	रा	क	सि	न
का	■	रा	मा	य	ण	■	के
र	स्सी	■	त्रा	ण	■	शू	ल

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में भवन संबंधी विवाद का सामना करना पडेगा. वर्ष के मध्य में रचनात्मक कार्यो में सफलता मिलेगी. व्यर्थ वाद विवाद से मतभेद बढेगा. वर्ष के अन्त में व्यापार में प्रगति होगी. सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नवीन योजनाओं का विस्तार होगा.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को व्यापार में उन्नति होगी. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को वाहन का सुख प्राप्त होगा. कर्क राशि के व्यक्तियों को व्यर्थ वाद विवाद एवं मतभेद में वृद्धि होगी. सिंह राशि के व्यक्तियों को रचनात्मक कार्यो में सफलता मिलेगी. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को राजकीय क्षेत्र सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता बनी रहेगी. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ प्राप्त होगा. मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को दूसरों के सहयोग के लिये तत्पर रहना पड़ेगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक कल्पनाप्रिय होगा, साहसी और निडर रहेगा, इसकी शिक्षा उत्तम होगी, किसी विशेष तकनीकी विद्या का ज्ञाता होगा, अपने लक्ष्य के प्रति निश्चयी होगा, पिता का भक्त रहेगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

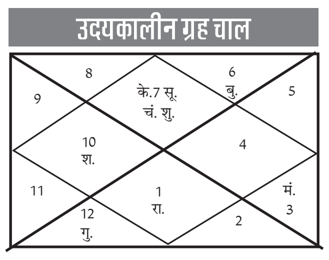

पंचांग

रा.मि. 11 संवत् 2083 चैत्र शुक्ल चर्तुदशी बुधवासरे प्रातः 6/16, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रे दिन 3/32, वृद्धि योगे दिन 2/19, वणिज करणे सू.उ. 5/52, सू.अ. 6/8, चन्द्रचार कन्या, पर्व- पूर्णिमा व्रत, शु.रा. 6,8,9,12,1,4 अ.रा. 7,10,11,2,3,5 शुभांक- 8,0,5.

व्यापार भविष्य

चैत्र शुक्ल चर्तुदशी को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से सोना, चांदी, के भाव में मंदी होगी, गुड़ खांड, शक्कर, उड़द, के भाव में वृद्धि होगी, कपास, सरसों, तिल, बिनौला, में वृद्धि होगी, वायदा मार्केट में बाजार का रूख देखकर कार्य करें, भाग्यांक 3657 है.

मेष- सहयोगी आपकी कार्यकुशलता और मेहनत का लाभ उठायेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, व्यापारिक शिथिलता रहेगी, शुभ संदेश मिलेगा.

वृषभ- नई योजनाओं की शुरूआत में परेशानी हो सकती है, ले देकर काम कराने की कोशिश सफल होगी, स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है.

मिथुन- जिद में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं, जोखिम से दूर रहें, धार्मिक कार्यो में लगन एवं रूचि रहेगी. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी.

कर्क- कार्यक्षेत्र में समझौता करना लाभकारी रहेगा, विवादित मामले सुलझने के आसार हैं, नौकरी में अनुकूलता रहेगी, सामाजिक कार्यो में मान सम्मान मिलेगा.

सिंह- नए संपर्क कैरियर बनाने में सहायक हो सकते हैं, दुविधा की स्थिति दूर होगी, स्थायी प्रयासों में धन प्राप्त होगा, मांगलिक कार्यो पर विचार होगा.

कन्या- कारोबारी विस्तार की संभावना है, आय में वृद्धि होगी, परन्तु अनावश्यक धन खर्च होगा, मित्रों से मतभेद हो सकता है, व्यापारिक लेनदेन के मामले सुलझेंगे.

तुला- कामकाज की व्यस्तता रहेगी, इच्छानुसार कार्य होंगे, भ्रमण मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होगी, लाभ होगा. संतान की उन्नति होगी.

वृश्चिक- सामूहिक कार्य में सबकी सलाह लेकर आगे बढ़े, सफलता मिलेगी, व्यर्थ की चिन्ता दूर होगी, कार्यो में इच्छित सफलता मिलेगी.

धनु- न चाहते हुये भी समझौता करना पड़ सकता है, प्रापर्टी संबंधी मामले सुलझने की उम्मीद है, पारिवारिक सुख एवं साधनों में वृद्धि होगी.

मकर- मेहमानों की आवाजाही रहेगी, झूठ बोलकर लोग भ्रमित करेंगे, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, धैर्य एवं नम्रता से सहयोग मिलेगा, तनाव से बचें.

कुम्भ- दुविधा की स्थिति आगे बढ़ने में बाधक होगी, अपनों के कारण मुश्किल हो सकती है, आर्थिक समस्याओं का सरलता से समाधान होगा, नौकरी में परिश्रम होगा.

मीन- प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के आसार हैं, आय में वृद्धि होगी, मित्रों की मदद करेंगे, नौकरी में परिश्रम अधिक रहेगा, प्रवास का योग है.

SUDOKU 7347

9		2		4	1	7		
1						6		
5	7	3	2				4	
				9	4	8		
4		7				9		6
		5	8	3				
	3				6	5	9	1
		6						7
		9	1	8		2		4

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7346

5	4	9	1	8	3	2	6	7
1	2	6	4	9	7	3	5	8
3	8	7	5	2	6	1	4	9
8	7	1	3	4	2	6	9	5
9	5	3	6	1	8	7	2	4
2	6	4	7	5	9	8	1	3
4	3	5	2	7	1	9	8	6
6	9	2	8	3	4	5	7	1
7	1	8	9	6	5	4	3	2